India and foreign interference in India's internal matters was discussed with the Russian President.

(b) President Yeltsin, in response, stated that India must keep its integrity, must stay united and undivided. He added that Russia intended to support India in its position on Kashmir.

Dissolution of the SAARC

1770. SHRI SURESH PACHOURI :
SHRI IQBAL SINGH :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government considers that SAARC has become redundant due to hostile activities by Pakistan and other member countries against India which is a prominent member of the Organisation;

(b) if so, whether Goverment proposes to suggest for the dissolution of the SAARC; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH) : (a) No Sir. In terms of SAARC Charter bilateral and contentious issues between member States are strictly excluded from SAARC deliberations. SAARC has thus been insulated from bilateral controversies in order to be able to concentrate fully on selected programmes of regional cooperation. All SAARC decisions including items to be covered or discussed are governed by the principle of unanimity. India remains firmly committed to the Charter of SAARC and SAARC as an organisation which will foster regional stability and progress.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Pending Passport Application in Hyderabad

1771. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of passport applications pending with Hyderabad Passport Office; and

(b) what steps are being taken to expedite the issue of passports in Hyderabad ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA) : (a) The number of passport applications pending in the Hyderabad Passport Office as on 12-2-93 was 31,314.

(b) Government have taken a number of measures to expedite the issue of passports which *inter alia* include increasing the supply of booklets, augmenting the staff strength and streamlining procedures for issue of passports.

जकार्ता में हुए गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाया जाना

1772. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने जकार्ता में आयोजित गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में काश्मीर का मुद्दा उठाने का प्रयास किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रया क्या है और

(ग) क्या इस अवसर पर भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के बीच कोई बातचीत हुई थी और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हाँ

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने उत्तर देने के अपने अधिकार का प्रयोग किया और बलपूर्वक कहा कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है तथा हमेशा रहेगा। अगर पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहे तो शिमला समझौते में संबंधित किसी भी विषय पर बातचीत की रूप रेखा मौजूद है। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने इस बात का भी उल्लेख किया कि पाकिस्तान ने गुटनिरपेक्ष

आन्दोलन में द्विपक्षीय मसलों को उठाकर आन्दोलन की परम्परा को तोड़ा है क्योंकि इस मंच पर उन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सकता है जो इस आन्दोलन में एकजुटता स्थापित करते हों।

(ग) जकार्ता में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन के अवसर पर 3 सितम्बर 1992 को हमारे प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बातचीत की थी। मंत्रिस्तर पर भी बात चीत हुई थी। इस बात पर बल दिया गया था कि दोनों देशों के बीच तनाव की मुख्य वजह यह है कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध तोड़फोड़ और आंतकवाद को समर्थन दे रहा है। यह अस्वीकार्य है और इसे बन्द किया ही जाना चाहिए जिससे कि सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बन सके।

सोवियत संघ से अलग हुए प्रत्येक गणराज्य में भारतीयों की संख्या

1773. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ से अलग हुए और स्वतन्त्र देशों का रूप ले चुके प्रत्येक गणराज्य में कितने भारतीय रह रहे हैं; और

(ख) क्या वे अपने भविष्य के प्रति आशंकित हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) इस विषय पर अधिकृत जानकारी देना कठिन है क्योंकि वह सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास कोई पद्धति नहीं है कि इन गणराज्यों में भारतीय नागरिक हमें अपने प्रवास की जानकारी दें। तथापि, कुछ देशों के सम्बन्ध में हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है यह नीचे दिए अनुसार है :

देश	छात्र	अन्य	योग
रूस	1961	250	2211
उक्रेन	1041	15	1056
बेलारूस	141	--	141
आर्मेनिया	160	--	160
अजरबेजान	86	10	96
लत्विया	49	--	49
मोल्दोवा	6	--	6
जार्जिया	104	--	104
एस्टोनिया	1	--	1

तथापि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि छात्रों की संख्या सही नहीं हो सकती है क्योंकि सार्वजनिक सलाह सूचनाओं के जारी होने के बाद से, जिनमें यह सलाह दी गई थी कि छात्रों को निजी आधार पर भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में नहीं जाना चाहिए। छात्रों की ओर से अपने आपको हमारे मिशनों में पंजीकृत कराने में हिचकिचाहट हो रही है।

(ख) 21 दिसम्बर 1991 को अल्मा आता में अपने शिखर सम्मेलन में भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के 11 गणराज्यों के राज्याध्यक्षों में स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रकुल के गठन की घोषणा की, राष्ट्रकुल के सदस्य राज्यों ने अपनी संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार उन अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की गारन्टी दी है जो भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के साथ हुई सन्धियों और करारों के फलस्वरूप हैं।

Visa to visiting students—Denial by UK

1774. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the move of United Kingdom to deny visas to visiting students even for short period;